PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 310 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | सोमवार, 25 मई, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

मारवाड़ की पुकार

मुख्यमंत्री जी, म्हारे अठे भी पधारो

पूर्वी राजस्थान के गांवों में सीएम के सीधे जनसंवाद को देखकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की ढाणियों के लोगों को मुख्यमंत्री दौरे का इंतजार

यहां दशकों पुरानी समस्याए जस की तस, अब जगी उम्मीद की 'किरण'

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

पूर्वी राजस्थान के धुआंधार दौरों और ईआरसीपी के जरिए जल क्रांति की अलख जगाने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मारवाड़ क्षेत्र और सरहदी जिलों के ग्रामीणों की उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं। थार के रेगिस्तान से अब एक ही सुर गूंज रहा है - 'मुख्यमंत्री जी, हमारे यहां भी आओ !' इस हिस्से के भी मुख्यमंत्री आप ही हो और हमें आपसे अपार उम्मीदें हैं। क्योंकि यह क्षेत्र खासकर बाड़मेर और जैसलमेर जो दूरस्थ रेत के धोरों में फैला है, जहां दशकों से बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इससे पहले आप जैसे संवाद और चौपालें देखने को नहीं मिली, लेकिन अब हमें आपसे खास आस बन गई है। पूर्वी राजस्थान के गांवों में सीएम के सीधे जनसंवाद को देखकर अब बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों की ढाणियों में रहने वाले लोग पलकें बिछाए मुख्यमंत्री के दौरे का इंतजार कर रहे हैं।

मारवाड़ की आवाज

धोरों तक पहुंचे सीधे जनसंवाद :

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले कुछ समय से पूर्वी राजस्थान के जिलों में लगातार एक्टिव हैं, जिससे वहां विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिली है। इसी तर्ज पर अब मारवाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि जब सूबे के मुखिया खुद धरातल पर आते हैं, तो बरसों से अटकी फाइलें मिनटों में क्लियर होती हैं। बाड़मेर-जैसलमेर के सुदूर सरहदी गांवों के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री राजधानी से निकलकर सीधे रेतीले धोरों के बीच चौपाल लगाएं, ताकि सीमावर्ती इलाकों की जमीनी हकीकत और जनता का दर्द सीधे उन तक पहुंच सके।

बाड़मेर-जैसलमेर की मुख्य मांगें, जिन पर टिकी हैं नजरें

"बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के ग्रामीणों के पास मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए प्राथमिकताओं की एक लंबी फेहरिस्त है।

रिफाइनरी और स्थानीय रोजगार

पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के आसपास के गांवों के युवा चाहते हैं कि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के पुख्ता अवसर मिलें।

सौर ऊर्जा हब का लाभ

जैसलमेर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड एनर्जी हब बन रहा है, लेकिन स्थानीय गांवों को अभी भी निर्बाध बिजली और सीएसआर फंड के तहत विकास का इंतजार है।

सरहदी पेयजल संकट

गर्मी की शुरुआत के साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के टेल एंड (आखिरी छोर) पर बसे बाड़मेर-जैसलमेर के गांवों में पानी की किल्लत बढ़ जाती है, जिसके स्थायी समाधान की मांग ग्रामीण सीधे सीएम से करना चाहते हैं।

मजबूत कनेक्टिविटी

भारत-पाक सीमा से सटे गांवों को मुख्य जिला मुख्यालयों और मंडियों से जोड़ने के लिए सड़कों के सुदृढ़ीकरण की जरूरत है।

'जब मुखिया कदम रखता है, तो सुधरती है प्रशासनिक व्यवस्था'

मारवाड़ के वरिष्ठ ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे की आहट मात्र से ही पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ जाता है। बाड़मेर की 'चौहटन' से लेकर जैसलमेर की 'सम' और 'पोकरण' विधानसभा के दूर-दराज गांवों के लोग इस आस में हैं कि सीएम का कारवां जल्द ही जयपुर से मरुधरा के इस हिस्से की ओर कूच करेगा। पूर्वी राजस्थान में विकास का रोडमैप तैयार करने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मारवाड़ के इन सरहदी जिलों की 'पुकार' पर कब मुहर लगाते हैं और थार के धोरों का दौरा कर पश्चिमी राजस्थान को क्या सौगातें देते हैं।

पश्चिमी राजस्थान के जिले दूसरे जिलों की तुलना में काफी पिछड़े

बाड़मेर : क्षेत्रफल में बहुत बड़ा, सुदूर ढाणियों में पानी-बिजली का गंभीर संकट। बॉर्डर इलाके में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं है।

जैसलमेर: देश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, कठिन रेतीले धोरे, पानी के लिए मीलों का सफर और खराब कनेक्टिविटी।

बालोतरा : नवसृजित जिला प्रदूषण की मार झेल रहा है। रिफाइनरी के बावजूद स्थानीय रोजगार का अभाव।

जोधपुर: इस क्षेत्र का मुख्य केंद्र, लेकिन इसके ग्रामीण और संभाग के अंतर्गत आने वाले दूर-दराज के इलाके आज भी पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं।

बीकानेर: अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा जिला, जहाँ के ग्रामीण अंचलों में सिंचाई और पेयजल की भारी किल्लत रहती है।

जालौर: साक्षरता दर (विशेषकर महिला साक्षरता) के मामले में राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार।

पाली: औद्योगिक प्रदूषण (कपड़ा उद्योग) और भूजल स्तर में भारी गिरावट की मार झेल रहा क्षेत्र।

एस जयशंकर ने रूबियो के सामने रखा 5 सूत्रीय एजेंडा, कूटनीतिक संवाद और सुरक्षित समुद्री व्यापार को बताया अहम

नई दिल्ली।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत के पांच सूत्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करती है, बिना बाधा के समुद्री व्यापार का पक्ष लेती है, और व्यापार और संसाधनों का 'एक हथियार' के तौर पर इस्तेमाल करने का कड़ा विरोध करती है। हैदराबाद हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका विभिन्न क्षेत्रों में नियमित संपर्क और रणनीतिक समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, 'यह सचिव (रूबियो) की पहली भारत यात्रा, लेकिन उनके पद संभालने के बाद से हम लगातार संपर्क में रहे हैं। इसमें वाशिंगटन डी.सी. और न्यूयॉर्क में मुलाकातें शामिल हैं, और अन्य कार्यक्रमों के दौरान भी बातचीत हुई है।

राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन स्थल 2029 तक होंगे तैयार, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनेगा मुख्य केंद्र

नई दिल्ली

राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी अहमदाबाद को करनी है। अभी इसमें चार साल का समय बाकी है, लेकिन आयोजकों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइए जानते हैं इसे लेकर क्या प्लान बनाया गया है।राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहे अहमदाबाद को देश की खेल राजधानी बनाने की कमर कस ली गई है। 2030 में इन खेलों के लिए स्टेडियमों और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का जाल बिछाने की तैयारी हो गई है। कुछ स्टेडियम व स्पोर्ट्स कांप्लेक्स तैयार हैं, जबकि बड़ी संख्या में अन्य स्टेडियमों और कांप्लेक्स का निर्माण 2029 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मुख्य केंद्र बनाने की तैयारी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद मोदी स्टेडियम को खेलों का मुख्य केंद्र बनाने की तैयारी

कर ली गई है।

इस स्टेडियम के आसपास 335 एकड़ के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एन्क्लेव स्थापित किया जा रहा है

इसमें एक्वेटिक सेंटर, टेनिस सेंटर, मल्टीपरपज एरीना शामिल हैं।

इसके अलावा शहर में एथलेटिक, फुटबाल, हॉकी स्टेडियम के अलावा शूटिंग रेंज स्थापित की जा रही है।

गांधीनगर में बिछेंगे दो एस्ट्रोटर्फ

गुजरात सरकार की ओर से इस वक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अलावा 835 करोड़ रुपये की लागत से वीर सावरकर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण कराया जा चुका है। इस कांप्लेक्स में एक्वेटिक स्टेडियम वुशु, ताइक्वांडो का हाई परफॉरमेंस सेंटर, अत्याधुनिक इंडोर हॉल और स्पोर्ट्स कम्यूनिटी सेंटर स्थापित किया जा चुका है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले से ही तैयार है। आईआईटी गांधीनगर में हॉकी के लिए दो एस्ट्रोटर्फ बिछाने की योजना है।

अमेरिका-ईरान 60 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत, खुलेगा होर्मुज

वाशिंगटन।

अमेरिका और ईरान एक ऐसे समझौते के करीब हैं जिसमें 60 दिन का संघर्ष विराम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में संभावनाओं की ओर इशारा किया, वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने भी 'एमओयू पर काम जारी' कहकर सकारात्मक संकेत दिए। इस बीच एक रिपोर्ट '60 डे डील' की बात कर रही है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं जिसमें 60 दिनों के संघर्ष विराम विस्तार का प्रस्ताव शामिल है। इस अवधि के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोला जाएगा, ईरान को स्वतंत्र रूप से तेल बेचने की अनुमति होगी और उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर बातचीत की जाएगी।.

यह जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, समझौता ज्ञापन के तहत इन 60 दिनों के दौरान होर्मुज बिना किसी टोल शुल्क के खुला रहेगा। ईरान उन समुद्री बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटाने पर भी सहमत होगा जिन्हें उसने कथित तौर पर बिछाया है, ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रह सके।

रॉकेट और न्यूक्लियर प्लांट को मिलेगा स्वदेशी कच्चा माल, बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले रेयर अर्थ एलिमेंट्स

केन्द्रीय खान मंत्रालय ने कॉम्प्लेक्स के तीन ब्लॉक्स के तकनीकी मूल्यांकन का कार्य किया आवंटित

लोक टुडे/जयपुर

पश्चिम राजस्थान का बालोतरा जिला रिफाइनरी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना से देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ सामरिक और आर्थिक सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। यहां सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का ऐसा भंडार मिला है, जो भारत को रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध करवाने और देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होगा।

केन्द्रीय खान मंत्रालय की टेक्निकल कम कॉस्ट कमिटीज की संयुक्त बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया है। हाल ही में आयोजित इस बैठक में बताया गया कि कॉम्प्लेक्स के तीन भागों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई), हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स (एचआरईई) और क्रिटिकल रेयर मेटल्स का विशाल भंडार मिला है। इन ब्लॉक्स के तकनीकी मूल्यांकन

के लिए तीन कंपनियों को कार्य भी आवंटित कर दिया गया है।

सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एक ज्वालामुखी कुंड है, जो 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स के सर्वेक्षण में नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं। इन एलिमेंट्स का उपयोग एयरोस्पेस इंजन के लिए सुपरअलॉय मेटेरियल के साथ ही चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उपकरणों में उपयोग होने वाले सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट में किया जाता है। वहीं, परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल तकनीक, रोबोटिक्स,3 माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक प्रसंस्करण में इन दुर्लभ खनिज का इस्तेमाल किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और अन्य हाई-एंड तकनीकों के प्रयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दुर्लभ खनिजों की खोज और अनुसंधान को बढ़ावा देने में राजस्थान अग्रसर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एवं सिवाना ग्रेनाइट में रेयरअर्थ एलिमेंट एवं हेवी रेयरअर्थ एलिमेंट उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वहीं, इस संबंध में खान विभाग एवं संबंधित जिला कलक्टर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करें, जिससे काम में तेजी आ सके। वहीं, राज्य सरकार रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना भी कर रही है। यह केंद्र दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास में महती भूमिका निभाएगा। इसी के साथ, राज्य सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एटॉमिक, मिनरल्स डॉयरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एवं रिसर्च आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ साझेदारी कर ऐसे खनिजों की खोज और अनुसंधान को नई गति प्रदान कर रही है।

उल्लेखनीय है कि देश में स्वच्छ ऊर्जा एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और तकनीकी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति देने वाले लिथियम से लेकर रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों की खोज इस मिशन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस मिशन का लक्ष्य हरित अर्थव्यवस्था में भारत को एक वैश्विक प्लेयर के रूप में स्थापित करना है।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

21वीं सदी में दहेज हत्याएं

यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि 21वीं सदी के इस युग में भी दहेज प्रताड़ना और हत्या से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। इन दिनों ऐसे ही दो मामले चर्चा में हैं। एक नोएडा की त्विषा शर्मा की अपनी ससुराल भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है और दूसरा ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर का। दीपिका के स्वजन यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी की दहेज के कारण जान ले ली गई। भोपाल के मामले ने तो इतना तूल पकड़ा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआइ को सौंपने का फैसला किया। दीपिका के भी स्वजन अपनी बेटी की मौत के मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।

> 21वीं सदी में भी दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले चिंताजनक रूप से सामने आ रहे हैं, जैसे नोएडा की त्विषा शर्मा और ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर के मामले। यह दर्शाता है कि दहेज एक सामाजिक बुराई के रूप में अब भी मौजूद है, जो संपन्न परिवारों को भी प्रभावित करती है और केवल कानून से खत्म नहीं हो सकती।

दीपिका के परिवार के लोगों की मानें तो उन्होंने उसकी शादी में एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए और वर पक्ष को बहुत से उपहार दिए थे, फिर भी और दहेज की मांग हो रही थी। त्विषा शर्मा के ससुराल वालों पर भी दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने की विवशता है कि दहेज के मामले केवल गरीब-अशिक्षित परिवारों तक ही सीमित नहीं हैं। चूंकि दोनों ही मामलों की जांच जारी है, इसलिए अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि कई बार दहेज प्रताड़ना के आरोप मिथ्या होते हैं और यह भी किसी से छिपा नहीं कि दहेज निवारक अधिनियम उन कानूनों में से है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग को लेकर उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चिंता जता चुके हैं, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि दहेज प्रताड़ना के सारे मामले झूठे होते हैं। यह एक कटु सच्चाई है कि कई बार वधुएं दहेज के कारण इतना प्रताड़ित होती हैं कि वे आत्महत्या कर लेती हैं। तथ्य यह भी है कि दहेज हत्या के मामलों में सजा होती रहती है। ऐसे मामले सभ्य समाज के लिए शर्म की बात हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि बेटी के विवाह में स्वेच्छा से उपहार देने वाले माता-पिता को कई बार वर पक्ष की बेजा मांगों को भी मानना पड़ता है। वास्तव में ऐसे मामलों की गिनती करना कठिन है, जिनमें दहेज मांगा जाता है। कुछ मामलों में तो विवाह के बाद भी दहेज की मांग होती है। ऐसा उन युवतियों के साथ भी हो रहा है, जो नौकरी करती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2024 में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज हुए। हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि दहेज एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे बीच अब भी मौजूद है। इस बुराई को केवल कानून के सहारे खत्म नहीं किया जा सकता। इसमें समाज का सहयोग आवश्यक है। दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले यही बताते हैं कि हम अभी आदर्श समाज बनने से दूर हैं।

बदलते मौसम का बढ़ता खतरा

उत्तर और मध्य भारत के दस से अधिक राज्य इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहे हैं। अधिकांश स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा पहुंचा है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए मैदानों से पहाड़ की ओर जाते हैं, लेकिन अब कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी लू चलने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा में जहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री को पार कर गया है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार की रात पिछले चौदह वर्षों में सबसे गर्म रही। बढ़ते तापमान की तपिश ने न केवल आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि इससे कृषि का कार्य भी प्रभावित हो रहा है और कई जगह फसलों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हर साल मौसम में इतना ज्यादा उतार-चढ़ाव आखिर क्यों हो रहा है। जाहिर है कि यह जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक ताप का ही नतीजा है, जिससे मौसम का प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो रहा है। तापमान का बढ़ना सिर्फ मनुष्य और अन्य जीव-जंतुओं को शारीरिक रूप से ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर व्यापक होता है। अत्यधिक गर्मी से प्राकृतिक जलस्रोत सूखने लगते हैं, जिससे पेयजल संकट पैदा हो जाता है। सिंचाई के बिना फसलें बर्बाद हो जाती हैं और कई दफा बुआई का कार्य भी प्रभावित होता है। यही नहीं, झुलसा देने वाली गर्मी के कारण लोग घरों से कम निकलते हैं और बाजारों की रौनक गायब हो जाती है। नतीजतन व्यापारिक गतिविधियां सुस्त पड़ जाती हैं और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। गर्मी की सबसे ज्यादा मार गरीब तबकों को ही झेलनी पड़ती है, जिनके पास संसाधनों की कमी होती है। सरकार की ओर से ऐसे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले, तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है।

> बढ़ते तापमान की तपिश ने न केवल आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि इससे कृषि का कार्य भी प्रभावित हो रहा है और कई जगह फसलों को नुकसान हो रहा है।

एआई अवतार और स्मृतियों का कारोबार

लेकिन इससे जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी गंभीर

डॉ. मुकुल श्रीवास्तव

एक दिन आप सोकर उठें और देखें कि आपके मोबाइल पर किसी ऐसे प्रियजन का वॉयस या वीडियो नोट उन्हीं के मोबाइल नंबर से मिले, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? इंटरनेट आज एक वास्तविकता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह मृत्यु के बाद भी हमारे जीवन से जुड़ा रहेगा। पढ़ने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, पर भारत में मृत व्यक्तियों के एआई अवतार बनाने और 'ग्रीफ टेक' (शोक तकनीक) का बाजार तेजी से फैल रहा है। हाल ही में, अजमेर शहर के कपड़ा व्यापारी जयदीप शर्मा के विवाह रिसेप्शन में स्क्रीन पर उनके स्वर्गीय पिता प्रकट हुए। उन्होंने नए जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद तो दिया ही, मौजूद मेहमानों से बात भी की। दरअसल, जयदीप ने स्थानीय टेक-क्रिएटर को खोजा था, जिसने उनके पिता की कुछ पुरानी तस्वीरों, पुराने वॉयस नोट्स और उनके व्यवहार के तौर-तरीकों का अध्ययन करके, एक मिनट का 'एआई डीपफेक अवतार' तैयार किया था। वैश्विक स्तर पर 'हियरआफ्टर एआई' और 'स्टोरीफाइल' जैसी कंपनियां अब बाकायदा इस 'ग्रीफ टेक' को एक बिजनेस मॉडल में बदल चुकी हैं। ये कंपनियां किसी व्यक्ति के पुराने चैट्स, वॉयस मैसेज और सोशल मीडिया डाटा के आधार पर उसका डिजिटल भूत या 'घोस्ट बॉट' तैयार कर रही हैं। भारत भी इस मामले में अपवाद नहीं है। प्रथम दृष्टया यह किसी भावुक परिवार का अपने दिवंगत प्रियजनों

> दुनियाभर में मृतकों के एआई अवतार बनाने का बाजार भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, पर इससे जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी गंभीर हैं।

के प्रति प्रेम व तकनीकी चमत्कार लग सकता है, पर जहां भावनाएं तीव्र होती हैं, वहां बाजार सबसे पहले जड़ें जमाता है। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म 'ग्रैंड व्यू रिसर्च' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 'इंड-ऑफ-लाइफ प्लानिंग' और 'डिजिटल लीगेसी सर्विसेज', जिसमें एआई अवतार और डिजिटल यादें सहेजना शामिल है, का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। मनोविज्ञान के अनुसार, किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद 'शोक मनाना' एक बेहद जरूरी मानसिक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। इन्सान पहले रोता है, तड़पता है, इन्कार की स्थिति से गुजरता है और अंत में उस शून्यता और सत्य को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ता है। पर 'ग्रीफ टेक' इन्सान को शोक की इन्कार अवस्था में ही हमेशा के लिए अटका कर रख देती है। जब आपके पास एक ऐसा घोस्ट बॉट या डिजिटल क्लोन हो, जो मृत व्यक्ति की तरह ही आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सके, उसकी आवाज में फोन पर बात कर सके या वीडियो कॉल पर दिख सके, तो आपका मस्तिष्क कभी उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाएगा। ऐसे में, ग्रीफ टेक तकनीक इन्सान को एक अंतहीन अवसाद और 'अवास्तविक दुनिया' में धकेल सकती है। एआई मृत व्यक्ति को एक 'इंटरैक्टिव प्रोडक्ट' में बदल रही है, जिसे कुछ रुपये देकर कस्टमाइज किया जा सकता है। यह तकनीक अमरता का एक ऐसा भयावह छलावा दे रही है, जो वास्तव में मानवीय गरिमा को तहस-नहस कर सकती है। क्या किसी मृत व्यक्ति के पुराने जीमेल, इंस्टाग्राम पोस्ट और व्हाट्सएप चैट्स को खंगालकर उसकी 'डिजिटल आत्मा' को फिर से बनाने का अधिकार उनके परिवार या टेक कंपनियों को होना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। मौजूदा भारतीय कानूनी ढांचे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी मृत व्यक्ति के 'डिजिटल अवतार' के निर्माण के लिए उसकी मरणोपरांत सहमति को अनिवार्य बनाता हो या यह स्पष्ट करता हो कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। यह स्थिति पहचान की चोरी और ब्लैकमेलिंग के रास्ते खोलती है। पश्चिमी देशों में 'प्रोजेक्ट दिसंबर' और 'सीयांस एआई' जैसी कंपनियां सस्ते में चैट लॉग्स के आधार पर मृतकों के टेक्स्ट बॉट बना रही हैं, जो चैटजीपीटी जैसे मॉडल्स पर चलता है और बॉट मृत व्यक्ति की स्टाइल में बात करता है। इनका उद्देश्य शोक में मदद करना है, पर इनसे उपजी चिंताएं ज्यादा गहरी हैं। कल को अगर ये कंपनियां दिवालिया हो जाएं या इस डाटा को किसी तीसरे पक्ष को बेच दें, तो मृत व्यक्ति की गरिमा और निजता का क्या होगा। एआई बॉट असली व्यक्ति नहीं है। वह कभी गलत, बढ़ा-चढ़ाकर या अपमानजनक जवाब दे सकता है, बॉट को किसी और के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मजाक, अश्लील कंटेंट, और राजनीतिक दुरुपयोग जैसे मुद्दे हो सकते हैं। इसलिए, स्मृतियां पुरानी तस्वीरों, संस्मरणों और दिलों में ही अच्छी लगती हैं न कि कोडिंग के जरिये कृत्रिम रूप से जिंदा किए गए 'डिजिटल भूतों' में। हेजेन- यह एक एआई आधारित वीडियो बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से उपयोगकर्ता केवल टेक्स्ट लिखकर असली जैसे दिखने वाले वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए महंगे कैमरे, स्टूडियो या बड़े सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती। यह खास तौर पर मार्केटिंग, सोशल मीडिया और पेशेवर कंटेंट बनाने में बहुत उपयोगी है। इसमें 100 से ज्यादा ऐसे डिजिटल इन्सानी अवतार मौजूद हैं, जो लिखी हुई स्क्रिप्ट को बिल्कुल इन्सानों की तरह बोलते हैं। यह किसी वीडियो का 175 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी कर सकता है और अनुवादित वीडियो बिल्कुल असली भी लगता है।

कॉकरोच जनता पार्टी: क्या सर्वभक्षी कॉकरोच किसी बदलाव का प्रतीक हो सकता है?

भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में प्राणियों और राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्हों में पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन मजाक में ही सही किसी राजनीतिक पार्टी का नाम किसी तुच्छ समझे जाने वाले जीव पर रखा जाए और सोशल मीडिया में उसके फॉलोअरों की बाढ़ आ जाए, ऐसा पहले शायद ही हुआ है। हैरानी की बात है कि एक मजबूत संगठन वाली सरकार भी 'कॉकरोच एप्रोच' से इतनी डर गई कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा दिया। हालांकि इस कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के स्वघोषित जनक अभिजीत दिपके ने दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट चालू कर अपनी मुहिम चालू रखी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आभासी जगत में नवोदित कॉकरोच जनता पार्टी समूचे सिस्टम में बदलाव की एक शुरुआती मगर अभिनव और गंभीर मुहिम है अथवा इसका अंजाम भी किसी तात्कालिक आंदोलन के नतीजे में धूमकेतु की माफिक उभरी और बाद में बोरिया बिस्तर समेटने वाली सियासी पार्टियों की तरह होगा?

चुनाव चिन्ह में 'जानवर'

वैसे भारत सहित कई देशों में राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को प्रतीकात्मक स्वरूप देने के लिए कोई न कोई प्राणी चुनते रहे हैं। जैसे कि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है। पूर्वोत्तर की एक पार्टी एमजीपी का प्रतीक शेर है। लेकिन मानव समाज में सर्वाधिक मजाक का विषय और हेय दृष्टि देखा जाने वाला प्राणी गधा है, वह सियासी पार्टियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। श्रीमती मेनका गांधी ने बहुत पहले लिखे एक लेख में बताया था कि दुनिया में 48 राजनीतिक दलों का प्रतीक चिन्ह गधा है, इनमें अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल है। गधे बेहद परिश्रमी होते हैं, लेकिन न तो बगावत करते हैं और न ही सवाल करते हैं। लेकिन सीजेपी ने तो कॉकरोच को अपना प्रतीक बनाया है। इसके पीछे तात्कालिक कारण भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा एक सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने तंज किया था कि देश में 'कॉकरोच' की तरह ऐसे युवा हैं, जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरी तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।' व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों ने इसे अपने पर हमला माना। अमेरिका में पढ़ रहे अभिजीत दिपके को भी

यह बात चुभी और उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल फेंका कि क्यों न सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। इसे व्यापक समर्थन मिला। इसके बाद एक्स पर एक गूगल फॉर्म जारी हुआ। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी लिखी एक तस्वीर के साथ कैप्शन था-सभी कॉकरोचों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। पार्टी जॉइन करने के लिए 4 जरूरी योग्यताएं बताई गईं- 'बेरोजगारी, आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन, एबिलिटी टू रेंट प्रोफेशनली।

उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल एक्स हैंडल- @CJP_2029, पार्टी की वेबसाइट cockroachjantaparty.org और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। इससे एक संदेश यह भी गया कि यह पहल कॉकरोच को समाज में मान्यता दिलाने और राजनीतिक दृष्टि से अन्य पार्टियों को चट कर जाने का भाव लिए हुए है। चूंकि आभासी दुनिया बिना हथियार के लड़ा जाने वाला महायुद्ध है, इसलिए स्थापना के महज पांच दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा फॉलोअर जुटा लिए। बताया जा रहा है कि इसमें हर घंटे 5 लाख फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं। यह आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट फालोअर्स से कहीं ज्यादा है। सीजेपी के हैंडल्स पर जो कंटेंट से बढ़ते यूथ कनेक्ट से इतना तो सिद्ध हुआ कि देश में बेरोजगार कितनी बड़ी संख्या में हैं। सोशल मीडिया पर इस की राजनीतिक प्रतिक्रिया होनी ही थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज देश का युवा भयंकर गुस्से में है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वह युवाओं से सीधा संवाद करे। पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आज़ाद ने नई पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसका समर्थन किया। राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादव ने कहा कि यह देश के युवाओं में व्यवस्था को लेकर दबे असंतोष की सोशल मीडिया अभिव्यक्ति है, जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। दूसरी तरफ नवजात सीजेपी पर अपना कानूनी मालिकाना हक जताने के लिए भी जंग शुरू हो गई है। मामला कॉकरोच जनता पार्टी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का है। इसके लिए दो लोगों ने आवेदन कर किए हैं। क्या इंटरनेट मीम और वायरल नामों पर भी मालिकाना हक तय किया जा सकता है? सोशल मीडिया यूजर्स इसे मीम ब्रांडिंग और डिजिटल कब्जे की नई लड़ाई बता रहे हैं। अगर किसी एक पक्ष को ट्रेडमार्क मिल जाता है, तो भविष्य में इस नाम के इस्तेमाल को लेकर कानूनी अधिकार भी तय हो सकते हैं। सीजेपी औपचारिक रूप से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है। इसकी वेबसाइट पर व्यंग्य में लिखा गया है कि ये 'कॉकरोचिस्तान के नो इलेक्शन कमीशन पर कॉकरोच एक्ट के तहत एक नॉन-रजिस्टर्ड पार्टी है।' तो क्या यह मुहिम सोशल मीडिया क्रांति के साथ ही खत्म हो जाएगी? सके पीछे कारण यह है कि अभिजीत दिपके 2020 से 2022 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। वो आप के लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार का मटेरियल बनाते थे। बाद में वो अमेरिका चले गए और वहां से भारत में राजनीतिक मुद्दों और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी का कोई सीरियस घोषित एजेंडा नहीं है। लेकिन उसने अपने मैनिफेस्टो में 5 वादे किए हैं-

- अगर सीजेपी सरकार में आती है, तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
- अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी का वोटिंग राइट छीनना आतंकवाद से कम नहीं।
- महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण होगा, न कि 33 प्रतिशत। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50प्रतिशत आरक्षण होगा।
- अंबानी और अडाणी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। 'गोदी मीडिया' एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी।

फिर से न उभरने पाएं माओवादी

श्रवण गुप्ता

माओवाद का जहर निकालने के बाद मोदी सरकार अब प्रभावित इलाकों की सुरक्षा और वहां विकास सुनिश्चित करने में जुट गई है। बीते दिनों बस्तर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यहां विकास न पहुंचने का कारण माओवाद को बताते हुए कहा कि गैर-भाजपा सरकारों ने तो माओवाद मुक्त अभियान में हमारा सहयोग किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। इस पर विचार करना आवश्यक है कि 1960 के दशक में बंगाल के नक्सलबाड़ी से उठा ये बवंडर कैसे 14 राज्यों के लगभग 150 जिलों तक फैल गया? कैसे माओवादी तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक लाल गलियारा बनाने में जुटे? आखिर वे कौन सरकारें थीं, जिन्होंने हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं करने वाले माओवादियों को फलने-फूलने दिया और उन्हें बिगड़ैल बच्चा कहकर आगे बढ़ाया? यह अकारण नहीं है कि पीएम मोदी कांग्रेस को माओवाद समर्थक बताते हैं। कांग्रेस का इतिहास माओवाद के समर्थन का भी रहा है। वह माओवाद को एक सामाजिक-आर्थिक समस्या बताती रही। इसी के चलते 1970-80 के दशक में माओवादी फैलते चले गए। 1990 के दशक की शुरुआत में माओवादियों ने जब छत्तीसगढ़ में बस्तर के साथ ओडिशा, आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर दण्डकारण्य आदिवासी राज्य बनाने के लिए हिंसक गतिविधियां तेज कीं, तब भी कांग्रेस की सरकारें निष्क्रिय बनी रहीं। इस दौरान सैकड़ों जवान बलिदान हुए और निर्दोष नागरिक मारे गए। आंध्र की वाइएसआर रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने तो 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप से समझौता वार्ता तक कर ली थी। हालांकि टीडीपी का रुख खिलाफ रहा। 2003 में माओवादियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर हमला भी किया था। एक समय माओवादियों ने दक्षिण में अपना जंक्शन बना लिया था, जिसे वे केकेटी जोनल कमेटी कहते थे। केकेटी यानी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। दक्षिण में माओवादियों का कितना असर था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने यहीं आइईडी ब्लास्ट की तकनीक लिट्टे से सीखी थी। माओवादियों ने कांग्रेस को भी घाव दिए। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की झीरम घाटी में उन्होंने घात लगाकर हमला किया, जिसमें राज्य कांग्रेस का लगभग पूरा नेतृत्व खत्म हो गया। इसके बाद कांग्रेस का रुख थोड़ा बदला, पर 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने माओवादियों के खिलाफ वैसा अभियान नहीं छेड़ा, जैसा आवश्यक था। जब बीती 31 मार्च माओवाद के खात्मे की डेडलाइन थी, तब तेलगांना की कांग्रेस सरकार ने कहा कि राज्य में किसी माओवादी का एनकाउंटर नहीं होगा। यही वजह रही कि देश के दूसरे हिस्सों में जब माओवादियों का एनकाउंटर हो रहा था, तब तेलंगाना से एक भी बड़े एनकाउंटर की खबर नहीं आई। छत्तीसगढ़ में आपरेशन के दौरान माओवादी भागकर तेलंगाना के जंगलों में शरण ले रहे थे, इसलिए वहां से सिर्फ माओवादियों के सरेंडर की खबरें आईं। माओवादियों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में अभियान चल रहे थे, लेकिन संघर्ष क्षेत्र बस्तर यानी दण्डकारण्य और अबूझमाड़ का जंगल था। इसी दण्डकारण्य से तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा की सीमा लगती हैं। यहां माओवादियों का जोर था। अबूझमाड़ से गढ़चिरौली-महाराष्ट्र की सीमा लगती है, जिसे पिछले सप्ताह आपरेशन अंतिम प्रहार के बाद आधिकारिक रूप से माओवाद से मुक्त घोषित किया गया। अकेली कांग्रेस ही माओवादियों के प्रति नरम नहीं थी। अनेक ऐसे समूह भी थे, जो उनसे सहानुभूति रखते थे।

होर्मुज संकट के बीच बढ़ी ऊर्जा चिंता, विकल्पों की तलाश में भारत की नई रणनीति

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद समूचे मध्यपूर्व के इलाके में जैसे जटिल हालात पैदा हुए हैं, उसका स्वाभाविक असर वैश्विक पैमाने पर ऊर्जा की आपूर्ति पर पड़ा। हालांकि जब दोनों पक्षों के बीच चौदह दिनों के युद्धविराम की घोषणा हुई थी, तब उम्मीद जगी थी कि अब शायद ईरान होर्मुज जलमार्ग को भी खोल दे और कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बहाल हो।

मगर उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता नाकाम रही और इसी के साथ होर्मुज जलमार्ग की बहाली की उम्मीद एक बार फिर मंद पड़ गई। आज हालत यह है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति शृंखला बाधित होने का जिन देशों पर ज्यादा असर पड़ा है, वे अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग बाधित होने के बाद तेल और गैस की व्यापक कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि रसोई गैस के विकल्प के रूप में बायोगैस सहित अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को हर हाल में बढ़ावा दिया जाए। दरअसल, होर्मुज जलमार्ग से वैश्विक जरूरत के बीस से पच्चीस प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति होती है।

भारत भी उन देशों में शामिल है, जिनकी खासी निर्भरता वहां से आने वाले ऊर्जा स्रोतों पर है। यही वजह है कि ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाई है और उसके बाद अमेरिका ने नाकाबंदी की, तब से देश घरेलू गैस और पेट्रोल-डीजल की व्यापक कमी का सामना कर रहा है। इस बीच सरकार ने रूस से तेल खरीद के रास्ते तैयार करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के रुख की वजह से उसमें भी कई अड़चनें पेश आ रही हैं। ऐसे में फिलहाल सबसे बेहतर उपाय यही है कि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का ढांचा तैयार किया जाए। इस लिहाज से देखें तो देश में बायोगैस सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों की जमीन मजबूत होती है, तो यह न केवल तात्कालिक स्तर पर समस्या का सामना करने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण होगा, बल्कि यह दूरगामी स्तर पर देश के व्यापक हित में होगा।

पश्चिम एशिया में एक ओर अमेरिका के रुख तो दूसरी ओर ईरान के जवाबी रवैये की वजह से न केवल भारत, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने संकट धीरे-धीरे गहरा रहा है। शायद इसीलिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक ने दुनिया को यह चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह और बिना किसी शर्त के जल्द नहीं खुला, तो दुनिया जल्दी ही 'रेड जोन' में प्रवेश कर सकती है, जहां तेल आपूर्ति सामान्य मांग को भी संभालने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएगी।

समस्या यह है कि एक ओर अमेरिका और इजराइल का सामना करने के क्रम में ईरान होर्मुज जलमार्ग को बाधित करने को एक कारगर रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इसे खोलने के लिए अमेरिका के कदम पीछे हटाने की शर्त रख रहा है। यह भी पढ़ें- होर्मुज जलमार्ग में अब कितने भारतीय जहाज फंसे हुए हैं? अधिकारी ने बताया क्या है सरकार की प्राथमिकता पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है।

इस क्षेत्र में तनाव की वजह से जहाजरानी गतिविधियों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। एक अधिकारी ने बताया कि होर्मुज जलमार्ग में अभी भी 14 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि अधिकारी होर्मुज और उसके आसपास की सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, इसी रास्ते से दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने कहा, हम होर्मुज जलमार्ग में लोडिंग के लिए टैंकर भेजने के संबंध में विदेश मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। अधिकारी के अनुसार, भारत इस क्षेत्र में जहाज तभी भेजेगा जब यह आकलन कर लिया जाएगा कि वहां परिचालन के लिए स्थितियां पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सेमीकंडक्टर सेक्टर पर संवाद

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान के लिए अपार संभावनाएं

प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्धः मुख्यमंत्री

जयपुर(नि.सं.)। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान के लिए बड़ा हिस्सेदार बनने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश इस क्षेत्र में निरन्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है और गत दो वर्षों में 450 फैक्ट्रियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत एक साल में 75 फैक्ट्रियां स्वीकृत हो चुकी हैं। साथ ही, इस योजना को लेकर केन्द्रीय कैबिनेट ने बजट को भी बढ़ाया है। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों और विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निवेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी यूनिट की स्थापना का लक्ष्य तय कर आगे बढ़े। इस कार्य में डबल इंजन की सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो स्वयं सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं। इसके साथ ही 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

भिवाड़ी में खुला प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिम से स्पेस तक और मोबाइल से मिसाइल तक, हर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य उन्हीं देशों और राज्यों का होगा जो इस क्षेत्र में मजबूत क्षमता विकसित करेंगे। प्रदेश में भी इसी माह पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का भिवाड़ी में शुभारंभ हुआ है।

पशुपालन मंत्री ने जारी किया दो वर्षों का रिपोर्ट कार्ड

दो साल बेमिसाल विकास पुस्तिका का किया विमोचन

जयपुर(नि.सं.)। पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने शनिवार को पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान विगत दो वर्षों में क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी उपलब्धियों पर आधारित विशेष दो साल बेमिसाल विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध जनों और भारी संख्या में क्षेत्र की जनता ने भाग लिया। विकास और सुशासन के दो वर्ष कार्यक्रम में मंत्री श्री कुमावत ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दो साल सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट कार्ड इस बात का प्रमाण है कि हमने जो वादे चुनाव के समय किए थे, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए दिन-रात काम किया है। मंत्री श्री कुमावत ने अतिथियों के साथ मंच से विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में क्षेत्र में स्वीकृत हुई सड़कों, पेयजल योजनाओं, गोशालाओं के अनुदान, मंदिरों के जीर्णोद्धार और दुग्ध उत्पादकों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि सुमेरपुर की जनता ने दो वर्ष पूर्व जो जिम्मेदारी सौंपी थी, आज उसका पूरा हिसाब लेकर आपके बीच खड़ा हूँ।

न्यूज इन बॉक्स

राजस्थान पुलिस का 'संडेज ऑन साइकिल' महाअभियान संपन्न

18 हजार से अधिक लोग फिटनेस संकल्प से जुड़े

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान पुलिस के नेतृत्व में रविवार को प्रदेशभर में संडेज ऑन साइकिल अभियान का एक विशेष और भव्य संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाने के उद्देश्य से आयोजित इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, जवानों और आम जनता सहित रिकॉर्ड 18,000 से अधिक प्रतिभागियों ने अत्यंत उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का प्रभावी संदेश पहुंचाना है, जो कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक फिट इंडिया मूवमेंट का एक अभिन्न हिस्सा है. डीजीपी के निर्देशन और खेल मंत्रालय के निर्देशों के तहत 75वां संस्करण यह विशेष आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के तहत राष्ट्रमंडल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की खेल संस्कृति को मजबूत करना है।

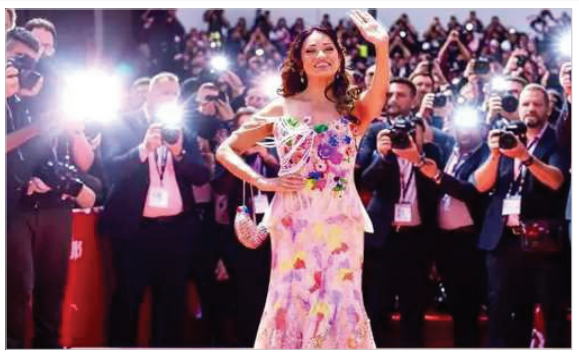

कांस के रेड कारपेट पर छाई मारवाड़ की बेटी

डॉक्टर सोनल परिहार ने बढ़ाया जोधपुर का मान, राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी ड्रैस पहनकर खींचा ध्यान

जोधपुर (नि.सं.)। फ्रांस में आयोजित विश्व प्रसिद्ध कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर इस बार मारवाड़ की बेटी और जोधपुर की डॉक्टर सोनल परिहार ने अपनी शानदार मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लिया। पारंपरिक भारतीय खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के संगम ने उन्हें सोशल मीडिया और फैशन जगत में चर्चा का विषय बना दिया। सोनल की इस उपलब्धि से जोधपुर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र में गर्व का माहौल है। जोधपुर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ और फैशन आइकन डॉ. सोनल परिहार ने 'कान्स' में भारत और राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। उनके रेड कारपेट लुक्स में राजस्थान की सांस्कृतिक झलक के साथ ग्लोबल फैशन का बेहतरीन मेल दिखा।

अजमेर के विकास में जुड़ा एक और स्वर्णिम अध्याय

राज्य सरकार आमजन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य कर रही हैः झाबर सिंह खर्रा

जयपुर(नि.सं.)। अजमेर के समग्र एवं आधुनिक विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। पंचशील नगर स्थित झलकारी बाई स्मारक के सामने लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। पहले चरण में इसमें 34 करोड़ रुपये खर्च तथा द्वितीय चरण में 36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही, किशनगढ़ के सिलोरा क्षेत्र में वेयरहाउस गोडाउन योजना का लोकार्पण एवं योजना की विवरणिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों की उपस्थिति ने विकास के इस संकल्प को जनभागीदारी का स्वरूप प्रदान किया। विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर के विकास का जो स्वप्न वर्षों पूर्व देखा गया था, वह आज चरणबद्ध रूप से मूर्त रूप ले रहा है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अजमेर भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन एवं मुख्यमंत्री के विकसित राजस्थान संकल्प के अनुरूप अजमेर को आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं वैश्विक पहचान वाले शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचशील क्षेत्र आज विकास की नई पहचान बनकर उभर रहा है। यहां कामकाजी महिला छात्रावास, साइंस पार्क, कन्वेंशन सेंटर तथा अन्य आधुनिक परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।

देवनानी ने रजत जयंती समारोह में की सहभागिता

सहकारिता और जनसेवा के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की भूमिका सराहनीय

जयपुर(नि.सं.)। पंजाब के राज्यपाल एवं केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया तथा राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी शनिवार को चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। इंदिरा प्रियदर्शिनी सभागार में आयोजित चित्तौड़गढ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के रजत जयंती वर्ष समापन एवं गौरव समारोह में उन्होंने सहभागिता की। समारोह में सांसद श्री सी. पी. जोशी, विधायकगण, बैंक के निदेशक, पूर्व निदेशक, सदस्य एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ने पिछले 25 वर्षों में जनविश्वास अर्जित कर क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने बैंक परिवार को रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सेवा, पारदर्शिता एवं विश्वास की भावना के साथ आगे भी कार्य करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता उसी का सहयोग करती है जो ईमानदारी से कार्य करता है। सहकारिता को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ने सराहनीय कार्य किए हैं।

भीलवाड़ा में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से दो युवकों की मौत

हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार; लोगों में आक्रोश

भीलवाड़ा(वि.सं.)। भीलवाड़ा में बिजौलिया थाना क्षेत्र में रविवार को हादसे में मोपेड सवार दो युवकों की मौत हो गई। पत्थरों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने दोनों युवकों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े, जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली भी पलटी खा गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर मौके से ड्राइवर हो गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

पेयजल व्यवस्थाओं के संबंध में ली समीक्षा बैठक

भीषण गर्मी में समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : पटेल

जयपुर(नि.सं.)। जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में पाल रोड स्थित पंचायत समिति लूणी सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राजस्व विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं पंचायती राज विभाग की पेयजल संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार भीषण गर्मी में समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली भोगीशैल परिक्रमा, नौतपा एवं भीषण गर्मी के मद्देनजर संभावित बढ़ती पेयजल मांग पर विशेष चर्चा की गई। मंत्री श्री पटेल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित की जाएं ताकि आमजन को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लूणी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल पेयजल की मांग पर लगभग 16.8 एमएलडी जल उपलब्ध हो पा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने 421 स्टूडेंट्स को किया सम्मानित

बोले-शिक्षा से ही खुद का और समाज का विकास संभव

पाली (वि.सं.)। पाली शहर के निकट गोल निबड़ा खेतावास रोड स्थित शनिधाम में रविवार को बाबा साहेब प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शनिधाम के महामंडलेश्वर स्वामी निजस्वरूपानंदपुरी के सान्निध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहे। आयोजन दाती सेवा संस्थान एवं वादी नट भाट जागृति संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। समारोह में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 421 छात्र-छात्राओं को बाबा साहेब शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री और संत निजस्वरूपानंदपुरी ने विद्यार्थियों को सम्मान प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।

मिशन निदेशक राजन विशाल का सीकर दौरा

हर घर जल लक्ष्य को समयबद्ध पूरा करने पर दिया जोर

योजनाओं की गुणवत्ता, डिजिटल मॉनिटरिंग एवं हर घर जल प्रमाणन कार्यों की समीक्षा

जयपुर(नि.सं.)। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से मिशन निदेशक श्री राजन विशाल ने सीकर जिले का दौरा कर विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं हर घर जल प्रमाणन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि प्रदेश में हर घर जल के संकल्प को समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।

जल जीवन मिशन एवं अमृत 2.0 योजनाओं का निरीक्षण

दौरे के दौरान मिशन निदेशक ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल योजनाओं झुन का बास, करणपुरा, सिहोट छोटी एवं लांपुवा (खंडेला) का निरीक्षण किया।

इसके साथ ही अमृत 2.0

जल संरक्षण

जल संरक्षण को बनाएं जीवन का प्रण, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन आंदोलन बनेगा

गांव-गांव में कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ जैसे जल स्त्रोतों की सफाई के साथ होगा दीप प्रज्वलन

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा 25 मई से 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' की शुरुआत की जा रही है। गंगा दशमी के शुभ अवसर पर प्रारंभ होने वाला यह अभियान विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य केवल जल स्त्रोतों की साफ-सफाई या पौधारोपण तक सीमित नहीं होकर समाज के प्रत्येक वर्ग को जल संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी से जोड़ते हुए इसे जीवन का प्रण बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के साथ पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं, महिलाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में वर्षा की अनियमितता और लगातार बढ़ती जल आवश्यकताओं को देखते हुए परंपरागत जल स्त्रोतों के संरक्षण को अभियान का मुख्य आधार बनाया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री

25 मई को टोंक में बीसलपुर बांध पर जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक के साथ अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री ईसरदा, बंध बरेठा और गालवा बांध का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के गंगा माता मंदिर में आरती और सुजानगंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। प्रदेशभर में इसी दिन कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों एवं अन्य जल स्त्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान जिले से लेकर ग्राम स्तर तक जल स्त्रोतों पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान, दीप प्रज्वलन और जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, जल संसाधन विभाग द्वारा जल उपयोगिता संगम और किसानों के सहयोग से नहरों एवं खालों की साफ-सफाई की जाएगी। साथ ही, नदी, बांधों, सरोवर एवं नहरों पर पूजन किया जाएगा। वहीं, नए जल संरक्षण कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन एवं पूर्ण कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा।

कुड़ी होद पर टैंकर जलापूर्ति, वितरण व्यवस्था एवं रिकॉर्ड का किया निरीक्षण

निर्बाध पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: जोगाराम पटेल

- भीषण गर्मी में पेयजल व्यवस्था का लिया विस्तृत जायजा, जल स्रोतों एवं वितरण तंत्र का किया निरीक्षण
- कायलाना झील, तख्तसागर एवं हाथी नहर पर जल आवक व प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा

जयपुर(नि.सं.)। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आमजन को निर्बाध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर शहर एवं लूणी विधानसभा क्षेत्र की पेयजल व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

कायलाना, तख्तसागर एवं हाथी नहर पर जल स्रोत एवं आवक व्यवस्थाओं की समीक्षा

नहरबंदी समाप्त होने के बाद जोधपुर की पेयजल आपूर्ति की प्रमुख आधारशिला कायलाना झील का निरीक्षण करते हुए मंत्री श्री पटेल ने कायलाना झील, तख्तसागर एवं हाथी नहर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पेयजल आपूर्ति से जुड़े तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हुए जल आवक, भंडारण एवं वितरण व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जल प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने तथा पेयजल वितरण व्यवस्था को सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने हाथी नहर के माध्यम से हो रही जल आवक एवं आगे की आपूर्ति व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक एवं बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह

केन्द्र व राज्य सरकार खेल व खिलाड़ियों को आगे बढाने के लिए प्रतिबद्ध : वन राज्यमंत्री

विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर किया सम्मानित

जयपुर(नि.सं.)। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलवर जिला बॉक्सिंग संघ द्वारा आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक एवं बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वन राज्यमंत्री श्री शर्मा ने 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक एवं बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर आयोजक मंडल को बधाई दी तथा राज्य स्तरीय इस आयोजन के लिए अलवर शहर को चुनने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अभिभावकों से आह्वान किया कि बेटों के साथ बेटियों को आगे बढने के अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेल व खिलाडियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारे जीवन में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। खेल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जीवन के हर सौपान पर प्रतिस्पर्धा होती है और खेल भावी जीवन में आने वाली प्रतिस्पर्धाओं के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से खिलाड़ी को तैयार करता है। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद व केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा अलवर संसदीय क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के साथ-साथ खेल के माध्यम से युवाओं को आगे बढने का प्लेटफार्म प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आधुनिक शिक्षा ई-लाइब्रेरी पर फोकस करते हुए निरन्तर युवा हित में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने अलवर के खिलाड़ियों को अलवर सांसद खेल उत्सव व अलवर टाइगर मैराथन के माध्यम से खेल व खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती भी प्रदान कर रहे है। उन्होंने कहा कि यहां जिस कोर्ट में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है वह भी अलवर सांसद श्री भूपेन्द्र यादव ने तैयार करवाया है। साथ ही यहा हॉकी का एस्ट्रॉटफ, सिंथेटिक ट्रेक, जीडी कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल, जिले में कई स्थानों पर स्टेडियम, खैरथल में बेटियों के लिए हॉकी एकेडमी आदि सौगातें भी दी हैं। उन्होंने कहा कि श्री यादव ने सांसद खेल उत्सव के उत्कृष्ट खिलाडियों के खेल को और अधिक निखारने के लिए समर कैम्प के माध्यम से सांई के प्रशिक्षित कोचों द्वारा खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण दिलाया गया है। इसके साथ ही संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए 133 ई-लाइब्रेरी तैयार कराई गई है। उन्होंने खिलाडियों को जीवन में आगे बढने एवं अपने खेल के माध्यम से अपने सपने साकार कर देश का नाम रोशन करने हेतु प्रोत्साहित किया। मंच सचालन शिक्षाविद श्री दिनेश शर्मा व श्री महावीर सिंह ने किया।

अधीक्षण अभियंता बढ़ाएं फील्ड विजिट

गर्मी में उपभोक्ताओं को मिले निर्बाध बिजली: चेयरमैन डिस्कॉम्स, आरती डोगरा

जयपुर(नि.सं.)। चेयरमैन डिस्कॉम्स सुश्री आरती डोगरा ने गर्मी के चुनौतीपूर्ण समय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर डिस्कॉम के सर्किल अधीक्षण अभियंताओं को बेहतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियंता फील्ड विजिट तथा निरीक्षण बढ़ाएं। इससे उन्हें अपने सर्किल के विद्युत तंत्र में आवश्यक सुधार करने तथा सुगम उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। सुश्री डोगरा विद्युत भवन में जयपुर डिस्कॉम के सभी ओएंडएम सर्किल अधीक्षण अभियंताओं के साथ गर्मी में विद्युत आपूर्ति, कनेक्शन, आगामी मानसून की तैयारियों, राजस्व प्राप्ति आदि विषयों पर समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने इस दौरान सर्किलवार डिफेक्टिव मीटर, विजिलेंस गतिविधियों, बिलिंग आदि की भी समीक्षा की। चेयरमैन डिस्कॉम्स ने कहा कि ग्रिड सब स्टेशनों, फीडर और अधीनस्थ डिवीजन एवं सब डिवीजन कार्यालयों के निरीक्षण पर जोर दिया जाए। इससे निचले स्तर तक लोड एवं विद्युत छीजत की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी और विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों पर रेस्पोंस टाइम को बेहतर किया जा सकेगा।

डिस्कॉम का पूरा तंत्र अलर्ट मोड पर

सुश्री डोगरा ने कहा कि तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण विद्युत तंत्र पर भी लोड बढ़ा है। ऐसी स्थिति में ट्रिपिंग अथवा फॉल्ट की आशंका से निपटने तथा उपभोक्ताओं को व्यवधान रहित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम का पूरा तंत्र अलर्ट मोड पर है। उन्होंने निर्देश दिए कि कॉल सेंटर, कंट्रोल रूम अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तकनीकी टीमें बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचें।

न्यूज ब्रीफ

जयपुर में विकसित भारत यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल 2026 का आयोजन

युवाओं को स्टार्टअप एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में मिलेगा मार्गदर्शन

जयपुर(नि.सं.)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में माय भारत, जयपुर द्वारा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद एवं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पहल के अंतर्गत विकसित भारत यंग प्रोफेशनल्स राउंडटेबल 2026 का आयोजन 25 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, रामबाग सर्कल, जयपुर में किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना, नवाचार आधारित सोच को बढ़ावा देना तथा स्टार्टअप एवं उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में महत्वपूर्ण बदलाव

अब तकनीकी अपग्रेडेशन पर मिलेगा एक करोड़ रुपये तक का अनुदान

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुपालना में राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इस नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि से प्रदेश के उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

राजस्थान की पहली नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी रही सफल

महात्मा गांधी चिकित्सालय में नेत्र कैंसर सेवाएं शुरू

जयपुर। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने राजस्थान में पहली बार आंख के कैंसर का इलाज नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी तकनीक से किया है। इस तकनीक का इस्तेमाल एक ऐसी महिला पर किया गया जिसकी एक आंख पहले ही खराब हो चुकी थी और दूसरी आंख में कैंसर हो गया था। अब इस अस्पताल में आंख के कैंसर के इलाज की नई सुविधा शुरू हो गई है। नेत्र कैंसर विशेषज्ञ डॉ रोलिका बंसल ने बताया- अब तक नेत्र कैंसर के मामलों में आंख को निकालना ही एकमात्र विकल्प माना जाता था, लेकिन अब नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी जैसी आधुनिक तकनीक से मरीज की आंख और दृष्टि दोनों को सुरक्षित रखने की संभावना बढ़ गई है। डॉ रोलिका बंसल ने बताया- महिला मरीज (72) की एक आंख लगभग 30 साल पूर्व संक्रमण के कारण नष्ट हो चुकी थी, ऐसे में दूसरी आंख को बचाना चिकित्सकों के लिए बड़ी चुनौती था। विशेषज्ञ टीम ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से सफल उपचार कर मरीज की दृष्टि एवं आंख को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की। रोगी अब स्वास्थ्य लाभ ले रही है। इस ऑपरेशन को नेत्र रोग विभाग, रेडिएशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, कैंसर रोग विभाग एवं निश्चेतना विभाग की संयुक्त टीम ने सफल बनाया।

नस्लीय टिप्पणी पर अमेरिकी विदेश मंत्री निराश

कहा- हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, वे अमेरिका के नुमाइंदे नहीं

नई दिल्ली(एजेंसी)। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियों और भेदभाव के सवाल पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान पूरे अमेरिकी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुबियो से अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद की घटनाओं पर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा, हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो ऑनलाइन या फिर सरेआम आपत्तिजनक बातें करते हैं, लेकिन इससे किसी देश की असली पहचान तय नहीं होती।

रूबियो ने भारतीय समुदाय के लोगों की तारीफ की

रूबियो ने कहा कि अमेरिका आज भी दुनिया के सबसे स्वागत करने वाले देशों में से एक है। उन्होंने कहा, ÷हमारे देश को दुनियाभर से आने वाले लोगों ने मजबूत बनाया है। वे अमेरिका आए, अमेरिकी समाज में शामिल हुए और देश की तरक्की में योगदान दिया। उन्होंने खास तौर पर भारतीय समुदाय की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज में बड़ा योगदान दिया है।

फिट इंडिया साइकिल संडेः एसएमएस स्टेडियम में कॉमनवेल्थ डे 2030 थीम पर भव्य आयोजन

मुख्य सचिव ने 5 किलोमीटर साइकिल चला कर दिया खेलों के प्रति जागरूकता और फिटनेस का संदेश

खिलाड़ियों, वरिष्ठ अधिकारियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने लिया भाग

जयपुर(नि.सं.)। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में रविवार को फिट इंडिया - साइकिल संडे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष इस आयोजन की थीम कॉमनवेल्थ डे 2030 रखी गई थी, जिसमें खिलाड़ियों, अधिकारियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्टेडियम परिसर के चारों ओर आयोजित साइकिल रैली रही। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवनशैली और कॉमनवेल्थ खेल 2030 के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसके साथ ही जुम्बा सत्र भी आयोजित किया गया, जिसने कार्यक्रम को और अधिक ऊर्जावान बना दिया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित हस्तियाँ उपस्थित रहीं। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सीआरपीएफ जवानों एवं अन्य प्रतिभागियों के साथ 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर देशभक्ति और खेल उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतना और कॉमनवेल्थ 2030 की तैयारी की दिशा में एक सार्थक शुरुआत है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें सीआरपीएफ के डीआईजी श्री बृजेश तथा सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट प्रमुख रहे। राजस्थान राज्य खेल परिषद के सचिव प्रवीण गुप्ता और वित्त सचिव टीना सोनी ने भी साइकिलिंग कार्यक्रम में स्वयं भाग लेकर युवाओं को प्रेरित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के अधिकारियों ने भी युवा भागीदारी और फिटनेस जागरूकता को प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व, सामुदायिक खेल भागीदारी और भारत के बढ़ते खेल परिवेश पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि जयपुर तथा पूरे राजस्थान में ऐसे और अधिक सार्वजनिक फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर बोले-इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिला

फॉलोअर्स का डेटा शेयर कर पूछा- इनमें 94% भारतीय

नई दिल्ली(एजेंसी)।कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रविवार को दावा किया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिल गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, हम वापस आ गए हैं, तुम भूल गए थे कि हम जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने कॉकरोच की इमेज भी शेयर की। इससे पहले शनिवार को उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी और पर्सनल अकाउंट को हैक किया गया है। वहीं, दीपके ने रविवार को X पर फॉलोअर्स डेटा शेयर कर बताया कि उनके 94त्न से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं।

एस जयशंकर ने रूबियो के सामने रखा 5 सूत्रीय एजेंडा, कूटनीतिक संवाद और सुरक्षित समुद्री व्यापार को बताया अहम

नई दिल्ली(एजेंसी)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत के पांच सूत्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करती है, बिना बाधा के समुद्री व्यापार का पक्ष लेती है, और व्यापार और संसाधनों का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का कड़ा विरोध करती है। हैदराबाद हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका विभिन्न क्षेत्रों में नियमित संपर्क और रणनीतिक समन्वय बनाए हुए हैं।

कांस फिल्म फेस्टिवल में छाया जयपुर का हवामहलः आशना वासवानी ने खादी को बनाया रेड कारपेट का हिस्सा

जयपुर(नि.सं.)। विश्व प्रसिद्ध कांस फिल्म फेस्टिवल-2026 में इस बार जयपुर की सांस्कृतिक विरासत और राजस्थान की कला ने खास पहचान बनाई। डिजाइनर आशना वासवानी ने खादी से तैयार किए गए खास आउटफिट्स में जयपुर के प्रसिद्ध हवामहल सहित कई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के डिजाइन उकेरकर रेड कारपेट पर भारतीय संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया। जयपुर की फैशन डिजाइनर आशना वासवानी ने कांस में अपनी क्रिएटिविटी और भारतीय शिल्पकला का शानदार प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। आशना न केवल कांस में अपने लेटेस्ट कलेक्शन के साथ पहुंचीं, बल्कि उन्होंने डेनिम और खादी जैसे फैब्रिक को हाई फैशन और रेड कारपेट कूट्योर का हिस्सा बनाकर नया इतिहास भी रच दिया। आशना वासवानी को पहली भारतीय डिजाइनर बताया जा रहा है, जिन्होंने पूरी तरह खादी और डेनिम फैब्रिक से रेड कारपेट गाउन तैयार किया। उन्होंने अपने इस विशेष डिजाइन को कांस के प्रतिष्ठित मंच पर खुद पहनकर भी प्रस्तुत किया। उनके इस डिजाइन ने फैशन इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींचा और अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत में चर्चा का विषय बन गया।

राजस्थान आवासन मण्डल **राजस्थान आवासन मण्डल की अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई**

42 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती भूमि अतिक्रमण मुक्त

जयपुर (नि.सं.)। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों की पालना में राजस्थान आवासन मण्डल ने बड़ी एवं निर्णायक कार्रवाई करते हुए टोंक रोड स्थित कृष्णा कुंज, बी-2 बाईपास, ग्राम चैनपुरा एवं दुर्गापुरा की 42 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती अवाप्तशुदा भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराकर पुनः कब्जा प्राप्त किया। मण्डल सचिव श्री गोपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के सहयोग से हुई इस व्यापक कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध कब्जे हटाए गए तथा भूमि पर मण्डल की संपत्ति संबंधी बोर्ड स्थापित किए गए। शेखावत ने बताया कि ग्राम चैनपुरा स्थित खसरा संख्या 7, 15 से 24, 26 से 31 तथा दुर्गापुरा स्थित खसरा संख्या 265 से 270 तक की कुल 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि मण्डल की अवाप्तशुदा संपत्ति है। इस भूमि की अवाप्ति अधिसूचना 10 जनवरी 1990 को जारी की गई थी तथा 5 दिसंबर 1991 को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अवार्ड जारी होने के बाद मण्डल ने विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया था।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रिक, प्रकाशन, संपादक - नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, हटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड, जयपुर - 302006 से मुद्रिक एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झेलना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) प्रकाशित प्रबंध संपादक - पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)